many cases of AIDS have so far been detected in the country and which State accounts for majority of the cases. I would also like to know what steps have been taken to check the disease.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

देश में बेकार पड़े रंगीन पिक्चर ट्यूब कारखाने

*261. श्री विश्वास राव रामाराव पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रंगीन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण करने के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किये गए कुछ कारखाने इस समय बेकार पड़े हैं ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कारखानों में उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी, नहीं । (ख) तथा (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सहायता

*264. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता दिए जाने के लिए कोई व्यापक योजना कार्यान्वित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इस योजना से कितने व्यक्ति लाभान्वित हो रहे है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो, तो क्या सरकार इस प्रकार की कोई योजना आरम्भ करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) राज्यों में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों उप केन्द्रों में सभी के लिए, जिनमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति शामिल है, निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध है । इसके अलावा अनुसूचित जाति-बहुल क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में सरकार ने आधार-भूत ढांचे के मानदण्डों को शिथिल कर दिया है और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों के लिए 30,000 एवं 5000 के बजाए क्रमशः 20,000 और 3,000 की आबादी का मानदंड रखा गया है ।

नरोरा आणविक विद्युत परियोजना के चारों ओर खाली क्षेत्र

*265. श्री राम नरेश यादव :
श्री राम जेठमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नरोरा आणविक विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के उत्पादन को प्रारंभ करने से पुर्व इस परियोजना के चारों ओर एक खाली क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ आसपास की कितनी जमीन अधिगृहीत की गई है ;

(ग) इस भूमि अधिग्रहण से कितने ग्राम और ग्रामवासी प्रभावित हुए हैं ;

(घ) क्या इन प्रभावित लोगों को पुनः बसा दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन्): (क) इससे पहले कि पहला यूनिट बिजली का उत्पादन करने के चरण में पहुंचे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित अनिवार्य आवश्यकता के रूप में नरोरा रिएक्टरों के चारों ओर 1.6 किलो मीटर के अर्धव्यास का एक अपवर्जन क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) 1.6 किलोमीटर अर्धव्यास के अपवर्जन क्षेत्र की सीमा के अन्दर कुल भूमि क्षेत्र लगभग 760 हैक्टेयर है जिसमें संयंत्र भवनों और संरचनाओं को स्थापित करने के लिए भी भूमि शामिल है । इस भूमि में से लगभग 580 हैक्टेयर भूमि निजी है तथा शेष भूमि सरकार और ग्राम समाज स्थानीय पंचायत की है ।

(ग) रिएक्टरों के चार ओर 0.8 किलोमीटर के अर्धव्यास की भूमि का अधिग्रहण करने से संबंधित कार्य परियोजना के पहले चरण में पूरा किया गया था । 0.8 से 1.6 किलोमीटर के अर्धव्यास के बीच की भूमि का अधिग्रहण दूसरे चरण में किया जा रहा है । दोनों चरणों में किए उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण को एक साथ जोड़ें तो इस अधिग्रहण के कारण तेरह गांवों की भूमि प्रभावित हुई है । तेरह गांवों में से केवल छः गांवों के 3959 व्यक्तियों (882 परिवारों) का विस्थापन आवश्यक है । शेष सात गांवों में व्यक्तियों को विस्थापित किए बगैर केवल भूमि का अधिग्रहण किया जाना है ।

(घ) दूसरे चरण में अधिग्रहण की गई भूमि से प्रभावित व्यक्तियों को राज्य सरकार के माध्यम से मुआवजा देने का काम पूरा होने वाला है तथा आशा है कि प्रभावित व्यक्तियों को अप्रैल 1989 तक पुनः बसा दिया जाएगा ।

(ङ) पहले चरण में लगभग 34 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था तथा दूसरे चरण में लगभग 900 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है । विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिए भूमि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया गया है तथा पुनः बसाने के लिए मकानों का निर्माण-कार्य प्रगति पर है ।

National missile testing range project at Baliapal in Orissa

*268. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state what is the progress made so far regarding the implementation of the National Missile Testing Range Project at Baliapal in Orissa?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI K. C. PANT): The land required for the National Range has been finalised. Work regarding resettlement and rehabilitation schemes for the families likely to be displaced from the range area is in progress.

The construction works for establishing the first Model Village, 50-bed Hospital, improvement of roads and Industrial Training Institute are in advanced stages.

A textile complex at a cost of Rs. 19 crores is expected to be completed soon near Baliapal

The work on other rehabilitation schemes such as leather complex, Agricultural Implements Factory, Extrusion Plant and development of Industrial Estate is also in progress.

The process of land acquisition would start in a progressive manner with the resettlement of the displaced families.